सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 24 APRIL TO 30 APRIL 2020 • VOLUME-33 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
No Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

डराने लगे हैं गुजरात के आंकड़े

अब देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की लिस्ट में 2 नंबर पर पहुंच गया है राज्य

नई दिल्ली, (एजेंसी): देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 21 हजार के पार हो चुके हैं। अब तक 21,355 मामले सामने आ चुके हैं। 3,960 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 683 की मौत हो चुकी है। इस बीच गुजरात में संक्रमण के साथ-साथ मौत के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। संक्रमण के मामले में महराष्ट्र के बाद अब गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में अबतक कुल केस 5,649 हैं तो गुजरात में यह आंकड़ा बढ़कर 2,407 पहुंच चुका है। आइए समझते हैं कि गुजरात अब किस तरह कोरोना संक्रमण का नया गढ़ बनकर उभर रहा है।

नए केसों में आधे से ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात से : देश के 2 समृद्ध राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना वायरस संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि बुधवार को सामने आए 1,273 नए मामलों में से 52 प्रतिशत से ज्यादा इन्हीं 2 पश्चिमी राज्यों से आए। बुधवार को महाराष्ट्र में 431 तो गुजरात में 229 नए मामले सामने आए। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जैसे दोनों ही राज्यों के मुख्य शहरों की स्थिति सबसे बुरी है। बुधवार को राजस्थान में 153, यूपी में 101 और दिल्ली में 92 नए मामले सामने आए।

कोरोना संक्रमण में 5 दिनों में छठे से दूसरे पर गुजरात : गुजरात में किस तेजी से कोरोना अपना पैर पसार रहा है, उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 5 दिन में यह राज्य देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की लिस्ट में छठे से दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 17 अप्रैल को गुजरात छठा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था।

नई मौतों में 79% महाराष्ट्र और गुजरात से

दोनों पश्चिमी राज्यों में संक्रमण के मामले तो तेज रफ्तार से बढ़ ही रहे हैं, मौत के मामले भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कल देश में कोरोना वायरस की वजह से 39 लोगों की जान गई। इनमें से 31 यानी 79 प्रतिशत मौतें महाराष्ट्र और गुजरात में हुईं। बुधवार को महाराष्ट्र में 18 और गुजरात में 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में 10 और अहमदाबाद में 9 मरीजों ने दम तोड़ा। रिकवरी रेट में मामले में गुजरात की स्थिति देश में सबसे बुरी गुजरात में नए मामलों का तेजी से बढ़ना तो चिंता बढ़ा ही रहा है, उससे भी ज्यादा यह बात डरा रही है कि रिकवरी रेट के मामले में सूबे की स्थिति देश में सबसे खराब है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,960 लोग ठीक हो चुके हैं यानी भारत में कोरोना संक्रमण के कुल जितने केस हैं, उनमें से करीब 19 प्रतिशत ठीक भी हो चुके हैं।

गुजरात में 100 से ज्यादा मौतें, देश में कुल मौतों का 15%

कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भी गुजरात अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में जहां अब तक 269 लोगों की मौत हुई है, वहीं गुजरात में भी यह आंकड़ा 100 के पार चला गया है। सूबे में बुधवार को 13 मौतों के बाद अब वहां कुल 103 लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह देश में कोरोना से हुई मौतों में अकेले गुजरात का हिस्सा 15 प्रतिशत के करीब है।

कोरोना की भेंट चढ़ी 6 माह की बच्ची

लुधियाना-फगवाड़ा, (ब्यूरो)

पंजाब के मालवा और माझा के मध्य सतलुज दरिया के पास बसे फगवाड़ा में रहने वाली 6 माह की नन्ही बच्ची रितिका जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी, की वीरवार को मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि बच्ची के दिल में छेद था और हार्ट सर्जरी के लिए उसे लुधियाना में दाखिल करवाया गया। फिर डॉक्टरों की सलाह के उपरांत जिंदगी बचाने के लिए उसे लुधियाना से पीजीआई के लिए चंडीगढ़ भेज दिया और वह कल से ही वेंटीलेटर पर थी। बच्ची को एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में टैस्ट के दौरान कोरोना पॉजीटिव पाया गया। जिसके बाद पूरे राज्य के लोगों में सहानुभूति की लहर उत्पन्न हो गई। लाखों हाथ उसकी जिंदगी बचाने के लिए रब्ब की खिदमत में उठे, फिर भी लाख कोशिशों के बाद उसे बचाया ना जा सका। फिलहाल उसे कोरोना कैसे हुआ? जांच का विषय है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने उसके पिता रामू समेत उसकी मां और नाना तक का कोरोना टैस्ट किया है। यहां बताना जरूरी है कि पंजाब में अब

● पंजाब में कोरोना से 17वीं मौत, लुधियाना के बाद चंडीगढ़ में दिल के छेद के लिए भर्ती थी मासूम रितिका

तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 17 तक जा पहुंचा है। डॉक्टरी सूत्रों के मुताबिक बच्ची का रात को ही बाथरूम आना बंद हो गया था और वह गुलूकोज पर थी। उसे फीड भी नहीं दी जा रही थी। बच्ची में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उसकी मौत हो गई। स्मरण रहे कि डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए 9 अप्रैल को लुधियाना स्थित अस्पताल में दाखिल करवाया था। कहा जाता है कि वेंटीलेटर पर रितिका अकेली थी और बीच में उसकी मां को दूर से ही देखने के लिए भेजा जा रहा था। मां-बाप समेत नाना-नानी का टैस्ट भी हुआ किंतु परिणाम सामने आने पर संतोषजनक निकले। अब सवाल उठता है कि आखिर मासूम रितिका को कोरोना कैसे हुआ? कहते हैं जिस वक्त रितिका का जन्म हुआ, उसका वजन ढाई किलो था और अब 6 माह की होने के बावजूद 3 किलो से आगे नहीं बढ़ी। कहा तो यह भी जाता है कि जब मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो उसे अभिभावकों ने जालंधर के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे, जहां करीब 36 दिन बच्ची का इलाज चला, और फिर उसका हार्ट फेलियर होने की शंका जताई गई, जहां पीजीआई रेफर किया गया। कहते हैं कि रामू की दयनीय स्थिति देखते हुए जालंधर के डीएम से उसका पास बना और एम्बूलेंस से वह पीजीआई पहुंचा था।

महाराष्ट्र के मंत्री को कोरोना

महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आहवाड़ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वह कितने लोगों के संपर्क में आए इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में 14 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई है और 778 नए मरीज सामने आए हैं। अकेले मुंबई में आज 6 लोगों की मौत हो गई। धारावी में 30 नए केसों से हड़कंप मच गया।

21 विदेशी गिरफ्तार

ठाणे पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली में मार्च महीने में तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए 21 विदेशियों सहित 25 लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि पृथक-वास की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

राज्यों पर कोरोना संकट से लड़ने के लिए नीति न थोपे केंद्र : कांग्रेस

नई दिल्ली, (ब्यूरो): कांग्रेस ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण लोगों के समक्ष जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनके समाधान के लिए केंद्र को जरूरी कदम उठाने के साथ ही राज्यों को इस महामारी से लड़ने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुसार काम करने देना चाहिए।कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल तथा संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए और इसके लिए उन्हें आर्थिक पैकेज दिये जाने चाहिए। कोरोना वायरस की लड़ाई राज्यों को लड़नी है, इसलिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाना चाहिए। केंद, के पास राज्यों का जो भी पैसा है, उसे संकट की इस घड़ी में उन्हें लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य समिति ने यह भी प्रस्ताव किया है कि राज्यों को अपनी परिस्थिति के हिसाब से कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष करने देना चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें अपनी नीति राज्यों पर नहीं थोपनी चाहिए। यह लड़ाई राज्य सरकारों को भी लड़नी है। इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों को आर्थिक रूप से मदद कर उन्हें उनके हिसाब से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई लड़नी देनी चाहिए। पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के मामले में भी चर्चा की और कहा कि लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हुई है।

राहुल गांधी और प्रियंका ने प्रवासी कामगारों को राहत देने की पैरवी की

नयी दिल्ली,(भाषा) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों के फंसे प्रवासी कामगारों को राहत प्रदान करने की पैरवी करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को इस काम को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए।पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि लॉकडाउन एक 'पॉज बटन' की तरह है और कोरोना मुक्त इलाकों में कारोबारी गतिविधियों की शुरुआत करने की जरूरत है।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ''प्रवासी कामगारों के मुद्दे को पहली प्राथमिकता के तौर पर हल करने की जरूरत है।''प्रियंका गांधी ने कहा, ''कोरोना वायरस से लड़ाई में करूणा महत्वपूर्ण है और पीड़ित के प्रति शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए।''उन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ ही हमें

जरूरी जांच और ऐहतियात बरतने के बाद प्रवासी कामगारों को घर लौटने की इजाजत देनी होगी। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, ''कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हालात संतोषजनक नहीं हैं। भारत सरकार को राज्यों के सामने पैदा हुए वित्तीय संकट और स्वास्थ्यकर्मियों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का समाधान करना होगा।''कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, एके एंटनी और अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बैठक में अपने विचार रखे।

कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र से मांगा पैकेज

कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र से वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर मोदी सरकार राज्यों का सहयोग नहीं करती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में शामिल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की ओर से जीएसटी का बकाया नहीं मिलने और अपनी सरकारों द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी केंद्र की ओर से उनके राज्य के लिए जीएसटी का 4400 करोड़ रुपये का बकाया जारी नहीं किया गया है।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय मदद नहीं करती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी।उन्होंने केंद्र से बड़े वित्तीय पैकेज की मांग की।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और विद्यार्थियों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र को नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकर इस मुद्दे पर चुप है।

हजार परिवारों को ग्रोसरी देंगे रजनीकांत

मुंबई, (ब्यूरो): दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत ने साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हजार परिवारों को ग्रोसरी देने का निर्णय लिया है । को रो ना वायरस के कहर के बीच फिल्म इंडस्ट्री के कई क ला का र लगातार किसी न किसी तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रजनीकांत का नाम भी इस सूची में शामिल है। फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया में 50 लाख रुपये दान करने के बाद अब रजनीकांत नदीगर संगम के एक्टर्स की मदद के लिए भी आगे आए हैं। रजनीकांत नदीगर संगम के करीब हजार कलाकारों को ग्रोसरी का सामान उपलब्ध कराएंगे। साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन (नदीगर संगम) के कई कलाकारों को रोजाना की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रजनीकांत ने हजार कलाकारों को ग्रोसरी उपलब्ध कराने का विचार बनाया है।

विदेशी क्रूज पर फंसे 146 भारतीय मुंबई पोर्ट पर उतरे

मुंबई, (ब्यूरो): महाराष्ट्र में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या पांच हजार का आंकड़ा पार करके 5 हजार 649 तक पहुंच गई है। वहीं, मौत की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। राज्य में अब तक 269 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, राहत की बात यह है कि अब तक प्रदेश में 789 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इस बीच, एक विदेशी क्रूज पर समुद्र में फंसे 146 भारतीयों को मुंबई बंदरगाह पर उतरने शुरू हो गये हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री मनसुख मांडविया से बात की थी।विदेशी क्रूज मरीला डिस्कवरी पर 146 भारतीय फंसे हुए हैं। भारतीय कर्मचारियों को उतारने के बाद क्रूज नॉर्वे के लिए रवाना हो गया। मुंबई के कई इलाके सील करने के बाद भी संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बुधवार को 309 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है। मुंबई में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,754 हो गई है।कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि केंद्रीय टीम का अनुमान है कि मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15 मई तक 6.56 लाख तक पहुंच सकती है। साथ ही, 30 अप्रैल तक यह संख्या 42 हजार हो सकती है।वहीं, पुणे डिवीजन में अब तक 851 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 62 की मौते हो चुकी है।

क्रूज पर मौजूद किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं हैं

मुस्लिम डिलीवरी ब्वाय से किराना लेने से मना करने पर केस दर्ज

ठाणे के कश्मीरा इलाके में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लेने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी संजय हजारे ने बताया कि आरोपी गजानन चतुर्वेदी (51) के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसने डिलीवरी बॉय से उसका नाम पूछा फिर सामान लेने से इनकार कर दिया।

धारावी में अब तक 189 संक्रमित : एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहां अब तक 189 संक्रमित मिल चुके हैं। बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्रीय टीम के साथ इलाके का दौरा किया था। धारावी में संक्रमण से अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है।

कोरोना वॉरियर्स को 20 हजार जोड़े जूते देंगी प्रियंका चोपड़ा

मुंबई, (ब्यूरो): बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कोरोना वॉरियर्स को 20 हजार जोड़े जूते देने का एलान किया है।कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। इस परेशानी के दौरान बॉलीवुड कलाकार आगे आ रहे हैं। इस फेहरिस्त में प्रियंका चोपड़ा का भी नाम शामिल है। कुछ दिनों पहले प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि उन्होंने कई संगठनों को फंड दिये हैं। इस लिस्ट में यूनिसेफ, फीडिंग अमेरिका, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नॉकिड हंगरी, गिव इं डि या , आ ई ए ए च वी , फ्रैंड्स ऑफ एसीमा और पीएम केयर फंड का नाम शामिल है। इसके बाद प्रियंका ने स्वास्थ्य कर्मियों को 20 हजार जोड़ जूते देने का एलान किया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका ने को रो ना वा य र स महामारी के बीच लॉस एंजिल्स में फ्रंटलाइन पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 10 हजार फुटवेअर दान करने का एलान किया है। इसके अतिरिक्त पूरे भारत में सार्वजनिक / सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए अतिरिक्त 10,000 जोड़ भेजे हैं।प्रियंका ने कहा, ''देश भर में हेल्थकेयर से जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मी और हमारे सच्चे सुपरहीरो हैं, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनकी हिम्मत, प्रतिबद्धता और बलिदान इस वैश्विक महामारी में असंख्य जीवन बचा रहे हैं।

इंदौर में मृतक संख्या 53, महामारी संबंधी सर्वेक्षण तेज

इंदौर (मध्यप्रदेश), (ब्यूरो): देश में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक इंदौर में एक और मरीज की मौत के बाद महामारी की चपेट में आकर दम तोड़ने वालों की तादाद बढ़कर 53 हो गई।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अ धि का री (सीएमएचओ) प्रवीण जड़िया ने बृहस्पतिवार को कहा, शहर के शासकीय मनोरमा राजे टीबी (एमआरटीबी) चिकित्सालय में 56 वर्षीय पुरुष की मंगलवार को मौत हुई थी। इसके साथ ही मृतक संख्या बढ़कर 53 हो गई।उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में जिले में कोविड-19 के 26 नये मामले सामने आए हैं। पुराने आंकड़ों में मामूली संशोधन के बाद जिले में अब इस महामारी के मरीजों की तादाद बढ़कर 945 हो गयी है। इनमें से 77 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।आंकड़ों की गणना के मुताबिक जिले में कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर बृहस्पतिवार सुबह तक 5.61 प्रतिशत थी। जिले में इस महामारी के मरीजों की मृत्यु दर पिछले कई दिन से राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बनी हुई है।सीएमएचओ ने यह भी बताया कि 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले इंदौर शहर में कोविड-19 को लेकर करीब 2,000 दलों की मदद से सर्वेक्षण जारी है।

पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए

डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कोरोना से लंबी चलेगी लड़ाई

जिनेवा/नयी दिल्ली (ब्यूरो): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस 'कोविड-19' को ''बेहद खतरनाक'' करार देते हुये चेतावनी दी है कि इसका कहर लंबे समय तक जारी रहेगा। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक तेद्रोस गेब्रियेसस ने कोविड-19 पर नियमित प्रेसवार्ता के दौरान बुधवार को कहा कि विभिन्न भू-क्षेत्रों में यह महामारी अलग-अलग चरणों में है। एक ही क्षेत्र के भीतर भी इसमें विविधता है। पश्चिमी यूरोप में या तो इसके नये मामलों में स्थिरता आ गयी है या वे घट रहे हैं। अफ्रीका, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका और पूर्वी यूरोप में मामले कम हैं लेकिन चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं।उन्होंने कहा ''अधिकतर देशों में यह महामारी अभी आरंभिक चरण है। कुछ देशों में जहाँ यह बहुत पहले आयी थी वहाँ दुबारा इसका प्रकोप बढ़ रहा है। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिये : हमें लंबा रास्ता तय करना है। यह वायरस लंबे समय तक हमारे बीच रहने वाला है।'' उन्होंने कहा कि निस्संदेह लॉकडाउन

यह वायरस 'बेहद खतरनाक' है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि दुनिया की अधिकतर आबादी में इसके संक्रमण का खतरा है इसका मतलब यह है कि इसका प्रकोप दुबारा बढ़ सकता है

और सामाजिक दूरियों के अन्य उपायों से कई देशों में इसके संक्रमण को धीमा करने में सफलता मिली है, लेकिन यह वायरस ''बेहद खतरनाक'' है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि दुनिया की अधिकतर आबादी में इसके संक्रमण का खतरा है। इसका मतलब यह है कि इसका प्रकोप दुबारा बढ़ सकता है। श्री तेद्रोस ने कुछ देशों में लॉकडाउन के विरोध की खबरों के बीच कहा कि जाहिर तौर पर कई सप्ताह से घरों में कैद रहकर लोग ऊब चुके हैं। वे सामान्य जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी और आजीविका दाँव पर है। उन्होंने कहा ''डब्ल्यूएचओ भी यही चाहता है और हम लगातार इसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम पहले के समय में वापस नहीं जा सकते। एक ''नये सामान्य'' की आवश्यकता है - एक ऐसी दुनिया जो अधिक स्वस्थ, अधिक सुरक्षित और (आपदाओं के लिए) अधिक तैयार हो।'' उन्होंने सदस्य देशों से कोरोना के हर संभावित मरीज की पहचान करने, उन्हें एकांतवास में भेजने, उनकी जाँच करने, उनके संपर्क में आये लोगों की पहचान कर उन्हें एकांतवास में भेजने और लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक तथा सशक्त करने के लिए कहा।उन्होंने बताया कि दुनिया के 78 प्रतिशत देशों में ही कोरोना से लड़ने संबंधी कोई योजना तैयार है। इसके मरीजों का पता लगाने के लिए सर्विलांस तंत्र 76 फीसदी देशों के पास और मामलों की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला परीक्षण की क्षमता 91 प्रतिशत देशों के पास है। चिंता की बात यह है कि 52 फीसदी देशों के पास इस लड़ाई में आम लोगों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है तथा इतने ही प्रतिशत देशों के अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में पीने के पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता के बारे में कोई मानक नहीं है।

त्रिपुरा में ओलावृष्टि से तीन घायल और 500 से ज्यादा बेघर

अगरतला, (ब्यूरो): कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के बीच त्रिपुरा के दो जिलों में बुधवार शाम भारी ओलावृष्टि की चपेट में आने से कम से कम तीन लोग घायल हो गये और 500 से अधिक लोग बेघर हो गये।ओलावृष्टि के कारण राज्य के सिपाहीजाला और खोवाई जिले के चारिलाम, गोलाघाटी और ताकरजाला क्षेत्रों के गांवों में सौ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा।प्रशासन ने पाँच राहत शिविर खोले हैं और बेघर हुए लगभग 550 लोगों को आश्रय प्रदान किया है। सिपाहीजाला में चार और खोवाई में एक राहत शिविर स्थापित किया गया है हालांकि शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है।

दखल

ऑनलाइन शिक्षा और चुनौतियां

अलग-अलग छात्रों और समूहों के साथ मिलकर कक्षाओं में पढ़ाई करने से बेहतर समझ विकसित होती है। इसके विपरीत, ऑनलाइन पढ़ाई से शिक्षा का सारा बोझ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो जाता है, जिसमें छात्र सिर्फ डिजिटल तकनीक और गैजेटों पर निर्भर हो जाता है और इसका सबसे घातक नतीजा यह होता है कि ज्ञान अर्जन एकांगी रूप ले लेता है।

ऑनलाइन शिक्षा व परीक्षा के संबंध में हाल में जिस तरह के फैसले हुए हैं, वे वक्त की मांग तो हैं लेकिन व्यावहारिकता की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे, इसमें संदेह है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों ने अपने यहां न केवल शिक्षण कार्य, बल्कि परीक्षा जैसे काम तक ऑनलाइन शुरू कराने का फैसला किया है। इस कवायद से छात्रों की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यावहारिक मुश्किलों और तकनीकी संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन शिक्षण की सुविधाएं सर्वसुलभ नहीं हैं और इसी वजह से छात्रों और शिक्षकों को इसमें तात्कालिक तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, दूसरी ओर हमारे सामने अब बदलती दुनिया में तकनीक के साथ चलने की चुनौती भी है। आज दुनिया के तमाम शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर हमें उनके साथ दौड़ में शामिल होना है तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल इतना भर है कि भारत जैसे देश में इसे आसानी से कैसे स्वीकार्य बनाया जाए। लॉकडाउन से जूझ रही दुनिया में अब ज्यादातर कामकाज ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं।

कहना न होगा कि जीवन का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन संस्कृति में ढलने को मजबूर हो चुका है। इसी क्रम में ऑनलाइन शिक्षा भी एक विकल्प के रूप में सामने आई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्कूली बच्चे तक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होंगे। लेकिन अब यह हो रहा है, भले अड़चनें कितनी ही क्यों न हों। भारत के शिक्षा जगत की जमीनी हकीकत दुनिया से अलग है। अमेरिका, जापान और पश्चिमी यूरोप के देशों में, जहां हर व्यक्ति तक तकनीक की पहुंच दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, वहां पर भी शिक्षाविदों के बीच में ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा के बारे में एक राय नहीं है। अमेरिका में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों की सफलता दर प्रत्यक्ष कक्षाओं के छात्रों की तुलना में आठवां हिस्सा ही है। लॉकडाउन के कारण देश भर में छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। यह स्थिति देश के स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में देखने को मिल रही है। इस तरह की आपात परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था विश्वविद्यालयों में लागू की गई और पाठ्यक्रम को पूरा मान कर ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की तैयारियां भी चल रही हैं।

हकीकत यह है कि न सिर्फ विभिन्न क्षेत्रीय शैक्षणिक संस्थान, बल्कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इस दिशा में कदम बढ़ाने को लेकर दुविधा में हैं। इसका बड़ा कारण है कि संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वे अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षण संस्थानों के पास तो फिर संसाधन हो सकते हैं, भले सीमित हों, लेकिन छात्रों का बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। यही वह प्रमुख बिंदु है जो ऑनलाइन शिक्षण और परीक्षा को लेकर सबको चिंतित कर रहा है। छात्रों की पढ़ाई बाधित होने का प्रतिकूल प्रभाव आगे जाकर रोजगार की तैयारियों पर भी पड़ेगा। ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों को नजरअंदाज करना इसके लक्ष्य में बड़ी बाधा साबित हो सकता है। छात्रों और शिक्षकों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे तत्काल इस प्रणाली को आत्मसात कर लें और ऑनलाइन एप, ई-रिसोर्स व अन्य ऑनलाइन शिक्षण के तरीकों से सामान्य दिनों की तरह शिक्षण गतिविधियां चलाते रहें। लेकिन व्यावहारिक रूप से क्या ऐसा संभव हो पाएगा, बड़ा सवाल है।

इस ऑनलाइन कवायद का नतीजा अब तक इस रूप में सामने आया है, जिसमें शिक्षक किसी भी तरह से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने औपचारिकता में लग गया है व बहुसंख्यक छात्र ऑनलाइन पद्धति की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह एक असाधारण दौर है और ऐसे समय में बेशक नए प्रयोगों की जरूरत है। चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी और विभिन्न विश्वविद्यालयों से लेकर कॉलेज के शिक्षक तक, सभी नए और सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वह हैं छात्र। हमारे विश्वविद्यालयों में विभिन्न पृष्ठभूमियों से छात्र आते हैं। इनमें से बहुत से छात्र पहले से ही जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आदिवासी पृष्ठभूमि या शारीरिक निशक्तता के आधार पर कई तरह की चुनौतियां झेल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे शहरों से आने वाले छात्रों का है जो मार्च में छुट्टियों में अपने घर चला गया। अपने घरों में इन छात्रों के पास किताबों सहित दूसरी अध्ययन सामग्री नहीं हैं। ऐसे में छात्रों के सामने सवाल है कि कैसे पढ़ाई करें। छात्रों की यह मुश्किल तकनीकी संसाधनों के अभाव की वजह से है।

छात्रों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे क्षेत्रों से आता है जहां इंटरनेट की समस्या है। ऐसे छात्रों की संख्या भी कम नहीं है जिनके पास लैपटॉप जैसी सुविधा नहीं है। स्मार्टफोन के सहारे पढ़ाई संभव नहीं है। इसी तरह निशक्तजन छात्रों की विशेष जरूरतों पर भी ध्यान देना होगा, जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वांछित तकनीक तक पहुंच नहीं है और जो शिक्षण संस्थानों में मुहैया कराए जाने वाले संसाधनों और सुविधाओं पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। यह विडंबना ही है कि ऑनलाइन शिक्षण का यह संकट विश्वविद्यालय व्यवस्था के हाशिये पर मौजूद दूरस्थ माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा में लंबे समय से चल रहे संकट का हूबहू रूप है। पिछले दशक में विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लें। यहां हर साल स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में एक लाख से ज्यादा छात्र दाखिला लेते हैं। ज्ञात हो कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में ज्यादातर छात्र सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं।

नियमित कॉलेजों में सीटों की कमी के कारण या आर्थिक दिक्कतों के कारण दाखिला न ले पाने वाले छात्र बेहद खराब ढंग से चल रही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां बिना कक्षाओं के ही पाठ्यक्रम पूरा कराना व गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-सामग्री का अभाव एक आम बात है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की पढ़ने की क्षमताएं भी भिन्न होती हैं। ऐसे में उनकी जरूरतों को सिर्फ प्रत्यक्ष कक्षाओं में ही बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। अलग छात्रों और समूहों के साथ मिलकर कक्षाओं में पढ़ाई करने से बेहतर समझ विकसित होती है। इसके विपरीत, ऑनलाइन पढ़ाई से शिक्षा का सारा बोझ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो जाता है, जिसमें छात्र सिर्फ डिजिटल तकनीक और गैजेटों पर निर्भर हो जाता है और इसका सबसे घातक नतीजा यह होता है कि ज्ञान अर्जन एक एकांगी रूप ले लेता है।

बेहतर हो कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए मौजूदा सत्र को थोड़ा-सा बढ़ाया जाए, ताकि स्थिति ठीक होने पर एक निश्चित समय-सीमा के लिए उनके लिए कक्षाएं और पीसीपी (पर्सनल कांटैक्ट प्रोग्राम) के सत्र आयोजित किए जा सकें। इसके बाद ही परीक्षाओं के लिए या तो अतिरिक्त आंतरिक परीक्षण के तरीकों को अपनाया जा सकता है या बाह्य परीक्षा की योजना बनाई जा सकती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षण संस्थानों में आए संकट से बाहर निकलने के लिए ऐसे उपायों पर अमल करें जिनमें सभी के हितों का समावेश हो।

विचार

पाक की बड़ी साजिश फेल

आतंकी और हिज्बुल का टॉप कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने के बाद अब पाकिस्तान कश्मीर में नई साजिश करने की कोशिश कर रहा है और पुलवामा पार्ट-2 की घटना उसी की ओर इशारा कर रही है। मगर अब वह इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएगा।

सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने गुरुवार को पुलवामा पार्ट 2 साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों का प्लान 40 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटकों वाले कार बम से सुरक्षा बलों को दहलाने का था लेकिन अलर्ट सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस खतरनाक आतंकी साजिश को 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की तर्ज पर प्लान किया गया था। उस आतंकी हमले को यादकर आज भी दिल दहल जाता है। जम्मू से 78 गाड़ियों के काफिले के साथ 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। दोपहर सवा 3 बजे अचानक विस्फोटकों से लदी एक कार काफिले में शामिल एक बस से टकराई। तेज धमाके के साथ बस और कार के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना तेज था कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे का इलाका उसकी आवाज से दहल गया। यह आत्मघाती हमला था जिसे अंजाम दिया था जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी आदिल अहमद डार।

सीआरपीएफ के 76वें बटालियन के 40 जवान शहीद हो गए। कई अन्य घायल हुए। पाक की शह पर हुए इस दिल दहला देने वाले कायराना हमले से पूरा देश तब तक उबलता रहा जब तक बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने शहीदों की शहादत का बदला नहीं ले लिया। हमले के 12वें दिन 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। जम्मू-कश्मीर पर दुनियाभर में दुष्प्रचार के बाद भी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इस मुद्दे पर किसी देश का साथ नहीं मिला। हताश-परेशान इमरान खान जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर 2020 से बौखलाए हुए थे लेकिन उनकी कोई भी नापाक चाल घाटी में सफल नहीं हुई। वहीं, सीमा पर भारतीय सेना की चौकसी ने पाक प्रयोजित आतंकवाद पर नकेल कस रखी है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना घाटी में आतंकियों के जरिए भारत को परेशान करने की साजिश में जुटे हुए हैं। भारत के मुस्तैद सुरक्षाबलों ने न केवल आज पुलवामा-2 को टाल दिया बल्कि पड़ोसी देश को चेतावनी भी दे दी कि उनसे नापाक मंसूबे भारत कामयाब नहीं होने देगा।

सीमा पर भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तानी सेना कश्मीर में मौजूद स्थानीय व विदेशी आतंकियों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलवामा पार्ट-2 की कोशिश को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आतंकियों से पकड़ी गई कार में करीब 40 किलो ह्वश्वष्ठ थी। इतना बड़े पैमाने पर विस्फोटक बिना पाक की मदद के उपलब्ध नहीं हो सकती है। साफ है कि पाक भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अभी भी लगातार साजिश रच रहा है। कश्मीर के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी रियाज नायकू के मारे जाने के बाद पाक कश्मीर में नई साजिश करने की कोशिश कर रहा है और मौजूदा घटना उसी की ओर इशारा कर रही है।

दूध उत्पादकों की चुनौतियां

यदि अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी उत्पादों के निर्यात की छूट दे दी गई तो भारतीय डेयरी उत्पादक अमेरिकी किसानों से किसी भी स्थिति में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। नतीजतन डेयरी उत्पाद से जुड़े जो 12 करोड़ लघु और सीमांत भारतीय किसान दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाएंगे।

दुनिया में दूध उत्पादन में अव्वल होने के साथ भारत दूध की सबसे ज्यादा खपत में भी पहले स्थान पर है। बावजूद इसके पशु पालकों की गिनती देश की आर्थिकी में नहीं की जाती है। इन्हें और मछुआरों को सामान्य किसानों में ही शामिल कर लिया जाता है। लेकिन हाल में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में दूध उत्पादकों और पशु पालकों भी सुध ली गई है। दो लाख करोड़ रुपए के कर्ज पशु पालकों को दिए जाएंगे। हालांकि मवेशियों और इनके पालकों का अगर ठीक से सरंक्षण करना है तो वन संरक्षण अधिनियम में सुधार कर पशुओं को आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में घास चरने की अनुमति देनी होगी। इससे एक साथ दो फायदे होंगे, एक तो ये जंगली घास, फल-फूल और पत्तियां खाएंगे तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, नतीजतन देश की आबादी को पौष्टिक आहार मिलेगा। इससे बीमारियां भी कम होंगी। दूसरा लाभ यह कि जो पशुधन दुर्घटनाओं में रोजाना बड़ी संख्या में मर रहा है, उसे जीवनदान मिल जाएगा।

देश के प्रत्येक नागरिक को औसतन दो सौ नब्बे ग्राम दूध रोजाना मिलता है। इस हिसाब से कुल खपत प्रतिदिन 45 करोड़ लीटर दूध की हो रही है। जबकि शुद्ध दूध का उत्पादन करीब 15 करोड़ लीटर ही है। दूध की लगातार बढ़ रही मांग से मिलावटी दूध का कारोबार गांव-गांव फैलता जा रहा है। दूध की कमी की पूर्ति सिंथेटिक दूध बना कर और पानी मिला कर की जाती है। यूरिया से भी दूध बनाया जा रहा है। बहरहाल, मिलावटी दूध के दुष्परिणाम जो भी हों, इस असली-नकली दूध का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान एक लाख 15 हजार 970 करोड़ रुपए का है। दाल-चावल की खपत से कहीं ज्यादा दूध और उसके सह-उत्पादों की मांग लगातार बनी रहती है। साल 2018 में देश में दूध का उत्पादन 6.3 फीसद बढ़ा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय वृद्धि दर 2.2 फीसद रही है। दूध की इस खपत के चलते दुनिया के देशों की निगाहें इस व्यापार को हड़पने में लगी हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी दूध का कारोबार करने वाली फ्रांस की कंपनी लैक्टेल है, जिसने भारत की सबसे बड़ी हैदराबाद की तिरुमाला दूध डेयरी को 1750 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डेयरी को चार किसानों ने मिल कर बनाया था। भारत की तेल कंपनी ऑयल इंडिया भी अब दूध कारोबार में प्रवेश कर रही है, क्योंकि दूध का कारोबार 16 फीसद सालाना की दर से बढ़ रहा है। बिना किसी सरकारी मदद के बूते देश में दूध का 70 फीसद कारोबार असंगठित क्षेत्र संभाल रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। लेकिन पारंपरिक ज्ञान से न केवल वे बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन में सफल हैं, बल्कि इसके सह-उत्पाद दही, छाछ, घी, मक्खन, पनीर, मावा आदि बनाने में भी मर्मज्ञ हैं। दूध का 30 फीसद कारोबार संगठित क्षेत्र जैसे डेयरियों के माध्यम से होता है। देश में दूध उत्पादन में छियानवे हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हैं।

14 राज्यों की अपनी दूध सहकारी संस्थाएं हैं। देश में कुल कृषि खाद्य उत्पादों व दूध से जुड़ी प्रसंस्करण सुविधाएं महज दो फीसद हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे सात करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी है। रोजाना दो लाख से भी अधिक गांवों से दूध एकत्रित करके डेयरियों में पहुंचाया जाता है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण सीधे शहरी और कस्बाई ग्राहकों तक भी दूध बेचने का काम करते हैं। जीवनदायी दूध में मिलावट कोई नहीं बात नहीं है। हमारी ज्ञान परंपरा में शुद्ध दूध में थोड़ा बहुत पानी मिला कर ही पीने का प्रचलन है, जिससे दूध को पचाने में आसानी हो। लेकिन दूध में मिलाए जाने वाले जिन हानिकारक तत्वों की जानकारी सामने आई है, वह हैरान करने वाली है। बाजार में मिलने वाला 68 फीसद दूध मिलावटी है जो यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, कृत्रिम चिकनाई, सफेद रोगन और पेंट तक मिला कर बनाया जा रहा है। तय है, इस तरह की अखाद्य वस्तुएं जब जीवनदायी दूध में मिलाई जाएंगी तो देश का युवा होता बचपन स्वस्थ्य कैसे रहेगा? जब विषैले तत्वों को मिला कर दूध बेचा जाएगा, तब वह भयंकर बीमारियों का सबब तो बनेगा ही।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2011 में दूध की गुणवत्ता नापने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया था। इस मकसद की पूर्ति के लिए एक हजार 791 नमूने देशभर से इकट्ठे किए गए थे। इनमें सभी 28 राज्य और पांचों केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे। लद्दाख उस समय स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश न होते हुए जम्मू-कशमीर का ही हिस्सा था। तब तेलंगाना अस्तित्व में नहीं आया था, इसलिए राज्यों की संख्या 28 ही थी। इन नमूनों में से 68 फीसद नमूने एफएसएसआई के मानकों पर खरे नहीं उतरे। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, झारखंड और दमन-द्वीप में हालात कुछ ज्यादा ही बदतर हैं। इस सर्वे से यह सच्चाई भी सामने आई है कि हम सबसे ज्यादा दूध इसलिए उत्पादित कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें मिलावटी दूध उत्पादन की मात्रा भी जुड़ी हुई है। इस व्यवसाय पर अमेरिका समेत अन्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका की इस मंशा को समझने के लिए भारत और अमेरिका के बीच होने वाले आयात-निर्यात को समझना होगा।

2018 में दोनों देशों के बीच 143 अरब डॉलर यानी दस लाख करोड़ का व्यापार हुआ। इसमें अमेरिका को 25 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। इसकी भरपाई वह दुग्ध और पोल्ट्री उत्पादों का भारत में निर्यात करके करना चाहता है। इस नाते उसकी कोशिश है कि इन वस्तुओं व अन्य कृषि उत्पादों पर भारत आयात शुल्क घटाने के साथ उन दुग्ध उत्पादों को बेचने की छूट भी दे, जो पशुओं को मांस खिला कर तैयार किए जाते हैं। दरअसल अमेरिका में इस समय दुग्ध-उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी लोगों में दूध की जगह अन्य तरल-पेय पीने का चलन बढ़ने से दूध की खपत घट गई है। इस कारण दूध किसान आर्थिक बदहाली के शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अमेरिका अपने किसानों को प्रति किसान साठ हजार डॉलर से ज्यादा (करीब 44 लाख रुपए) सालाना की सब्सिडी देता है। इसके उलट भारत में सब मदों में मिलाकर किसान को 16 हजार रुपए की सालाना की मदद दी जाती है।

भारतीय नियमों के अनुसार यदि भारत किसी देश से दुग्ध उत्पादों का आयात करता है तो उसके निमार्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि जिन मवेशियों के उत्पाद भेजे जा रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे जानवर के आंतरिक अंगों एवं मांस तो नहीं खिलाए जाते हैं। यह नियम 2003 से लागू है। हालांकि ऑनलाइन व्यापार के जरिए मांस युक्त आहार बिकता है। हमारे यहां गाय-भैंसें भले ही कूड़े-कचरे में मुंह मारती फिरती हों, लेकिन दुधारू पशुओं को मांस खिलाने की बात कोई नहीं सोच सकता।

ट्विटर

पुलवामा जैसी घटना दोहराने की साजिश रच रहे पाक को यह नहीं पता कि इस बार वह अपने मंसूबे में सफल हुआ तो पहले से भी ज्यादा करारा जवाब मिलेगा।

मारुफ रजा, रक्षा विशेषज्ञ

पाकिस्तान की कोई भी चाल भारतीय सेना कामयाब नहीं होने देगी। आतंकियों के सहारे वह जो कुचक्र रच रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब हर बार दिया जाएगा।

मुकुंद नरवणे, सेना प्रमुख

सत्यार्थ

सही आदमी का चयन

एक अत्यंत बुद्धिमान राजा था। उसको एक नौकर की जरूरत थी। जब नौकर रखना था, तो परीक्षण जरूरी था। तब उसने अनेक लोगों को बुलाया, क्योंकि नौकर बहुत काम करने वाला होता है, लेकिन आदमी बहुत खतरनाक भी होता है। कोई खतरनाक आदमी न आ जाए, इसके लिए ही परीक्षण जरूरी था। बादशाह को एक युक्ति सूझी। उसने उपस्थित लोगों में से तीन को सामने खड़ा करके कहा-बताओ, इत्तेफाक से मेरी दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए, तो तुम क्या करोगे? पहला तुरंत बोल उठा, हुजूर! आपकी दाढ़ी की आग तुरंत बुझा दूंगा। अपनी दाढ़ी की आग की चिंता नहीं करूंगा। दूसरा बोला कि जहांपनाह! पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और फिर आपकी दाढ़ी की चिंता करूंगा। तीसरा बोला-हुजूर! एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा। बादशाह ने तीनों व्यक्तियों के उत्तर सुनकर कहा-पहला आदमी अव्यवहारिक है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं, जो कठिन समय आने पर अपनी बात न सोचकर दूसरे की सोचता हो, अपनी नहीं, बल्कि दूसरे की चिंता करे। इसलिए यह आदमी या तो झूठा है या अज्ञानी। दोनों ही स्थितियों में वह रखने योग्य नहीं है। दूसरा स्वार्थी है। स्वार्थी आदमी किसी का भला नहीं करता। वह सदा अपनी बात सोचता है, अपना ही भला करता है। वह आदमी भी खतरनाक होता है। आखिरी में बादशाह ने कहा-तीसरा आदमी न अव्यवहारिक है और न स्वार्थी। वह व्यवहार के धरातल पर ही जिंदा है। इस प्रकार, बादशाह ने सही व्यक्ति का चयन कर उस तीसरे व्यक्ति को नौकरी दे दी और बाकी दोनों को वहां से रवाना कर दिया।

Mercedes-AMG GT R और AMG C 63 Coupe भारत में लॉन्च

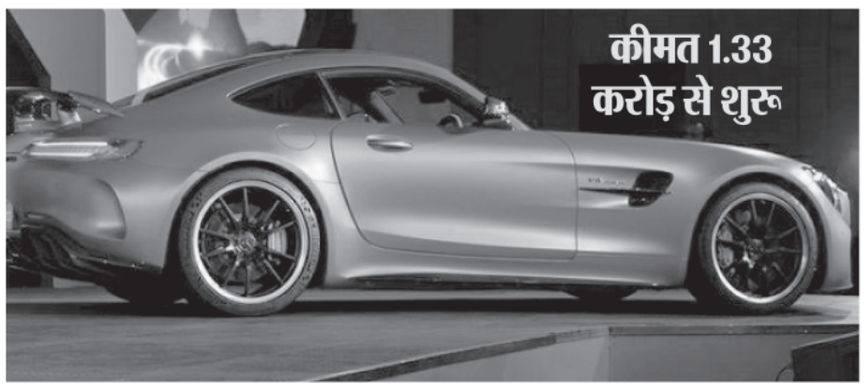

जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी Mercedes-Benz(मर्सिडीज-बेंज) ने भारत में 2020 Mercedes-AMG GT R (2020 मर्सिडीज-एएमजी जीटी आर) कार लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसके साथ भारत में नई Mercedes-AMG C 63 Coupe (मर्सिडीज-एएमजी सी 63 कूपे) भी लॉन्च की है। जब से इन कारों की शानदार तस्वीरों सामने आई थी, तब से कार प्रेमी इनकी लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे थे। दोनों मॉडल निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में भारत में लाए गए हैं। नए GT R को एक मिड-लाइफ अपडेट मिला है और लुक्स व डाइमेंशन के मामले में यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बेहतर हो गया है।

Mercedes-AMG GT R की खूबियां

कीमत: नई Mercedes-AMG GT R (मर्सिडीज-एएमजी जीटी आर) की भारत में एक्स-शोरूम 2.48 करोड़ रुपए रखी गई है।

डिजाइन: मर्सिडीज ने नई एलईडी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स के साथ AMG GT R को अपडेट किया है। इसमें एक रीडिजाइन किया गया एक्जॉस्ट और रियर डिफ्यूजर भी दिया गया है।

फीचर्स: केबिन की बात करें तो नई एएमजी जीटी आर में एक नया स्टीयरिंग व्हील और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। कार में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट हेड-यूनिट भी दिया है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है।

इंजन: Mercedes-AMG GT R में 4.0-लीटर, ट्विन-टर्बो वी8 इंजन मिलता है। यह 577 BHP और 700 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

स्पीड: मर्सिडीज का दावा है कि एएमजी जीटी आर सिर्फ 3.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इस कार की टॉप स्पीड 318 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कार में रियर-व्हील स्टीयरिंग स्टैंडर्ड मिलता है।

Mercedes-AMG C 63 Coupe की खासियतें

कीमत: नई Mercedes-AMG C 63 Coupe (मर्सिडीज-एएमजी सी 63 कूपे) एक 2-डोर कूपे कार है, जिसकी भारत में एक्स-शोरूम कीमत 1.33 करोड़ रुपए रखी गई है।

डिजाइन: नई C 63 Coupe कार में पैनामेरिकाना ग्रिल और नए एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं। कार के रियर में क्वाड एग्जॉस्ट और डिफ्यूजर दिया गया है। कार में 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

फीचर्स : नई सी 63 कूपे कार 3-स्पोक मल्टी-फंक्शन फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट हेड-यूनिट सेंटर कंसोल के ऊपर लगाई गई है, जिसमें कार्बन फाइबर लगा है। कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें काले और लाल रंग की लेदर अपहोल्सट्री दी गई है।

Hyundai ने लॉन्च किया सेडान वरना का नया संस्करण

इंटेलीजेंट तकनीक, बेहतर परफॉरमेंस और नए फीचर्स के साथ

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने हाल में सेडान वरना के नए संस्करण की पेशकश की, जिसकी दिल्ली में शोरूम कीमत 9.3 लाख से 15.09 लाख रुपए के बीच है। कंपनी ने बताया कि इस संस्करण का नाम दि स्प्रिटेड न्यू वरना है और इसमें बेहतर डिजाइन, इंटेलीजेंट तकनीक, बेहतर परफॉरमेंस और नए फीचर्स पर जोर दिया गया है। कंपनी के एमडी और सीईओ एस एस किम ने कहा कि वरना के नए संस्करण में भविष्य की डिजाइन, स्मार्ट संपर्क और सुपीरियर डायनामिक्स का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने बताया कि ये मॉडल बीएस-6 मानकों के अनुरूप है और 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल संस्करण तथा एक लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन संस्करण में उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक एस प्लस(डीजल) (बेस मॉडल) की एक्स-शोरूम कीमत 10,65,585 रुपए है। वहीं आरटीओ का 1,37,198 रुपए इन्श्योरेंस 50,818 रुपए और अन्य खर्चों को जोड़ने क बाद करीब नई दिल्ली में इसकी ऑन रोड कीमत 12,64,257 रुपए हो जाती है।

वरना के फीचर्स

कंपनी के मुताबिक इस 5-सीटर कार की फीचर लिस्ट में ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें पहले की तरह ही वेन्टीलेटेड फ्रंट सीटें और वायरलैस चार्जिंग की सुविधा भी है। गाड़ी के फेसलिफ्ट वर्जन में हैंड्स-फ्री बूट ओपनिंग, सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

फेसलिफ्टेड वरना में दो पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन दिए गए हैं। गाड़ी का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन क्रमशः 115 पीएस/144 एनएम और 120 पीएस/172 एनएम की पावर ट्यूनिंग के साथ आता है। वहीं, 1.5 लीटर डीजल इंजन 115 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।

पावर ट्रांसमिशन के लिहाज से इसके पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड एमटी और सीवीटी का ऑप्शन दिया गया है। वहीं, 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन (एमटी) और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (एटी) का विकल्प मिलता है। टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन रखा गया है। हुंडई वरना कुल 6 कलर विकल्पों फियरी रेड, टाइफून सिल्वर, फैंटम ब्लैक, स्टेरी नाइट, पोलर व्हाट और टाइटन ग्रे मैटेलिक में उपलब्ध है।

वैरिएंट	अनुमानित कीमत
एसएक्स डीजल	14.28 लाख
एसएक्स एटी डीजल	15.62 लाख
एसएक्स ऑप्शनल डीजल	16.5 लाख
एसएक्स otp एटी डीजल(top मॉडल)	17.84 लाख
एस(पेट्रोल)(बेस मॉडल	10.45 लाख
एसएक्स(पेट्रोल)	12.43 लाख
एसएक्स ivt(पेट्रोल)	13.86 लाख
एसएक्स opt(पेट्रोल)	14.6 लाख
एसएक्स ivt opt(पेट्रोल)	16.03 लाख
एसएक्स ऑप्शनल टर्बो(पेट्रोल)(top मॉडल)	16.13 लाख

नई Datsun Redi-GO, Renault Kwid या Maruti Alto, जानें कौन सी सस्ती कार बेस्ट

Datsun ने अपनी छोटी कार Redi-Go का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। पुराने मॉडल के मुकाबले Datsun Redi-Go फेसलिफ्ट के लुक में काफी बदलाव किए गए हैं। नई कार ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश दिखती है। साथ ही इसमें कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। रेडी-गो फेसलिफ्ट की मार्केट में सीधी टक्कर मारुति ऑल्टो और रेनॉ क्विड से होगी। यहां हम आपको इन तीनों कारों की खूबियों के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि इनमें से आपके लिए कौन सी कार बेस्ट है। बता दें कि ये तीनों कारें 0.8-लीटर इंजन में उपलब्ध हैं, जबकि रेडी-गो और क्विड में 1.0-लीटर इंजन का भी ऑप्शन है। यहां हम सिर्फ 0.8-लीटर इंजन के आधार पर बात कर रहे हैं।

पावर

दैटसन रेडी-गो फेसलिफ्ट का 0.8-लीटर इंजन 54 bhp की पावर और 72 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। मारुति ऑल्टो का इंजन 47 hp की पावर और 69 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। रेनॉ क्विड का 0.8-लीटर इंजन 53 hp की पावर और 72 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। तीनों कारों के इंजन के साथ 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है। पावर के आंकड़ों के आधार पर देखें, तो ऑल्टो में सबसे कम, जबकि नई रेडी-गो में सबसे ज्यादा पावर मिलती है।

माइलेज

नई दैटसन रेडी-गो के 0.8-लीटर इंजन का माइलेज 20.71 किलोमीटर प्रति लीटर है। ऑल्टो का माइलेज 22.05 किलोमीटर, जबकि क्विड के 0.8-लीटर इंजन का माइलेज 22.3 किलोमीटर प्रति लीटर है। माइलेज के आंकड़े ऑटोमोटिव रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के अनुसार हैं।

फीचर्स

दैटसन, रेनॉ और मारुति की इन कारों में एसी, फ्रंट पावर विंडो, एबीएस, ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, दो एयरबैग और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर मिलेंगे। नई रेडी-गो और क्विड में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जबकि ऑल्टो में

7-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। रेडी-गो और क्विड के टॉप वेरियंट्स में गाइड के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, जबकि मारुति ऑल्टो में यह फीचर नहीं है।

साइज

दैटसन रेडी-गो की लंबाई 3435 mm, चौड़ाई 1574 mm, ऊंचाई 1546 mm और वीलबेस 2348 mm है। मारुति ऑल्टो 3445 mm लंबी, 1490 mm चौड़ी और 1475 mm ऊंची है, जबकि इसका वीलबेस 2360 mm है। रेनॉ क्विड 3731 mm लंबी, 1579 mm चौड़ी, 1474 ऊंची है, जबकि वीलबेस 2422 है। साइज के मामले में रेडी-गो की लंबाई सबसे कम है, जबकि क्विड सबसे ज्यादा लंबी और चौड़ी है। ऊंचाई के मामले में रेडी-गो इन तीनों कारों में सबसे आगे हैं, जबकि क्विड और ऑल्टो की ऊंचाई लगभग बराबर है।

कीमत

दैटसन रेडी-गो फेसलिफ्ट के 0.8-लीटर इंजन मॉडल की कीमत 2.83 लाख से 4.16 लाख रुपए के बीच है। रेनॉ क्विड के 0.8-लीटर इंजन मॉडल की कीमत 2.92 लाख से 4.22 लाख रुपए के बीच है। वहीं, मारुति ऑल्टो के पेट्रोल मॉडल की कीमत 2.95 लाख से 3.90 लाख रुपए के बीच है। ये कीमत दिल्ली में एक्स शोरूम की हैं। शुरुआती कीमत के हिसाब से नई रेडी-गो सबसे सस्ती है, जबकि टॉप वेरियंट में ऑल्टो की कीमत सबसे कम है।

BS6 इंजन के साथ जल्द लॉन्च होगी TVS Scooty Zest 110, आ रहे हैं ये खास फीचर

TVS कंपनी अपनी Scooty Zest 110 के बीएस6 वर्जन पर काम कर रही है। उम्मीद है कि कंपनी इसे आने वाले कुछ हफ्तों में ही लॉन्च कर सकती है। बता दें कि कंपनी ने अप्रैल में बीएस6 Scooty Zest 110 का टीजर जारी किया था। इस दौरान कहा गया था कि Scooty Zest 110 को जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा।

TVS Scooty Zest 110 और TVS Victor : TVS ने अपने लगभग सभी टू-वीलर को बीएस6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपग्रेड कर दिया है। फिलहाल सिर्फ TVS Scooty Zest 110 और TVS Victor बाइक बीएस6 में अपडेट नहीं हुई हैं। हालांकि कंपनी अपने इन दोनों प्रोडक्ट पर काम कर रही है। मालूम हो कि टीवीएस स्कूटी जेस्ट 110 को खासतौर पर महिला ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

कई सालों से बाजार में मौजूद: टीवीएस जेस्ट कई सालों से बाजार में मौजूद है, लेकिन कंपनी ने अब इसे बीएस6 में अपडेट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इसके डिजाइन में बदलाव नहीं किए हैं। कंपनी ने इसमें 109.7 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगाया है, जो फ्यूल इंजैक्शन सिस्टम से लैस है। यह 7.8 बीएचपी पावर के साथ 8.4 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है।

फीचर्स : इस स्कूटर के अपडेटेड मॉडल में एलईडी हैडलैंप, इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल, एलईडी टेललैंप, डुअल टोन सीट कवर, स्मार्टफोन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, 19-लीटर स्टोरेज क्षमता, टैक्चर वाला फ्लोरबोर्ड, पार्किंग ब्रेक और ट्यूबलेस टायर्स जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। TVS स्कूटी जेस्ट 110 के अगले हिस्से में टेलिस्कोपिक फोर्क्स लगे हैं, वहीं पिछला हिस्सा हाईड्रॉलिक मोनोशॉक सेटअप के साथ है।

कीमत : स्कूटी के फ्रंट व्हील में 110एमएम ड्रम ब्रेक और पिछले व्हील में 130एमएम ड्रम ब्रेक दिया गया है। स्कूटी जेस्ट 110 को दो वर्जन में पेश किया गया है। वहीं इसकी कीमत की बात की जाए तो इसके मैट सीरीज की कीमत 54,025 रुपए है, जबकि हिमालयन हाई सीरीज मॉडल की कीमत 52,525 रुपए है। यानी बीएस4 मॉडल के मुकाबले नए स्कूटर के दाम 6,000 से 8,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं।

लक्जरी कार बनाने वाली बीएमडब्ल्यू ने लॉन्च की नई बाइक

कीमत 9.9 लाख से 11.5 लाख रुपए के बीच

बीएमडब्ल्यू मोटररैड ने भारतीय बाजार में अपनी एफ900 आर और एफ900 एक्सआर के नए संस्करण उतारे हैं। इनकी शोरूम कीमत 9.9 लाख से 11.5 लाख रुपए के बीच है। बीएमडब्ल्यू मोटररैड लक्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी बीएमडब्ल्यू की दोपहिया वाहन इकाई है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि दोनों मोटरसाइकिल पूरी तरह से बनकर आयात होंगी। इससे आशय है कि कंपनी इन्हें असेंबल नहीं करेगी। यह कंपनी के डीलर नेटवर्क पर उपलब्ध होगी।

बीएमडब्ल्यू एफ900 आर की कीमत 9.9 लाख रुपए है, जबकि एफ900 एक्सआर के स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 10.5 लाख रुपए और प्रो मॉडल की कीमत 11.5 लाख रुपए है। कंपनी के मुताबिक दोनों बाइक के फीचर्स नीचे दिए गए टेबल में हैं।

अवलोकन	बीएमडब्ल्यू	F 900 आर
एक्स-शोरूम कीमत	9.90लाख से शुरू	10.50 लाख से शुरू
रोड प्राइस प्राप्त करें	10.98लाख से शुरू	11.74 लाख से शुरू
माइलेज -	-	-
डिस्प्लेसमेंट	895 सीसी	895सीसी
इंजन टाइप	2-cylinder, 4-stroke 4 valves DOHC engine	2-cylinder, 4-stroke 4 valves DOHC engine
नंबर ऑफ सिलिंडर्स	2	2
मैक्स पावर	106.4 PS @ 8500 rpm	106.4 PS @ 8500 rpm
मैक्स टार्क	92 Nm @ 6500 rpm	92 Nm @ 6500 rpm
फ्रंट ब्रेक	डिस्क	डिस्क
रियर ब्रेक	डिस्क	डिस्क
ईंधन क्षमता	13 l	15.5 l
बॉडी टाइप	एडवेंचर टूरर बाइक्स	एडवेंचर टूरर बाइक्स

होंडा मोटरसाइकिल चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगी परिचालन

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने कहा कि वह देश में अपने सभी चार संयंत्रों को दो चरणों में शुरू करेगी। कंपनी के कर्नाटक स्थित संयंत्र में विनिर्माण गतिविधियां शुरू होंगी। सबसे पहले कर्नाटक के नरसापुर स्थित उसके सबसे बड़े संयंत्र को शुरू किया जाएगा और फिर अन्य तीन संयंत्र शुरू होंगे। एचएमएसआई ने कहा कि कंपनी के 300 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं में करीब 99 प्रतिशत को कामकाज के लिए जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं और वे उत्पादन शुरू करने की अग्रणी अवस्था में हैं। कंपनी ने बताया कि उसके 60 प्रतिशत से अधिक डीलरों ने भी अपना बिक्री एवं सेवा परिचालन शुरू कर दिया है।

Ola Electric 2021 में लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर, एम्स्टर्डम की कंपनी एटरगो का किया अधिग्रहण

Ola Electric Mobility (OEM), ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ओईएम) भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लॉन्च करने के लिए तैयार है। Ola Electric Mobility ने हाल ही में एम्स्टर्डम की Etergo BV (एटरगो बीवी) नामक कंपनी का अधिग्रहण किया है, जो इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने कहा कि उसने नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम स्थित एटरगो बीवी का अधिग्रहण किया है। इस कदम से भारतीय कंपनी को वैश्विक प्रीमियम इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। एक बयान के अनुसार, एटरगो की टीम एम्स्टर्डम से ही काम करती रहेगी।

पावर: Etergo BV को साल 2014 में स्थापित किया गया था और इसकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक Appscooter (एप स्कूटर) था। इस स्कूटर को अपनी डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में कई पुरस्कार से नवाजा गया। Appscooter एक बार फुल चार्जिंग पर 240 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसमें स्वैपेबल उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी का इस्तेमाल होता है।

2021 में होगी लॉन्च: ओला इलेक्ट्रिक ने इस सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य 2021 में भारत में अपना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पेश करना है। Etergo के अधिग्रहण से ओईएम की इंजीनियरिंग और डिजाइन क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी।

ओला को इलेक्ट्रिक स्कूटर से उम्मीदें: ओईएम के संस्थापक और अध्यक्ष भावेश अग्रवाल ने कहा कि मोबिलिटी का भविष्य इलेक्ट्रिक है, और कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन की मांग तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गतिशीलता का भविष्य इलेक्ट्रिक है और कोरोनावायरस संकट हमारे लिए दुनिया भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने का मौका दे रहा है। दुनिया भर में हर साल कारों की तुलना में दोपहिया वाहनों को बिक्री करीब दोगुनी होती है। इलेक्ट्रिक, डिजिटल कनेक्टिविटी फीचर्स वाले दोपहिया वाहन दुनिया भर में सबसे पसंदीदा शहरी आवाजाही के साधन के रूप में उभरेंगे और हर ग्राहक को सशक्त करेंगे। हम बढ़िया इंजीनियरिंग और डिजाइन से इन उत्पादों को भारत में बनाएंगे।

ओला को मिलेगा यह फायदा

ओला इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी) तंत्र बनाने पर काम कर रही है, जिसमें पूरे देश में व्यापक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क शामिल हैं। ओला दोपहिया और तीन पहिया वाहनों पर ध्यान देने के साथ शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग की व्यवस्था तैयार के लिए कई पायलट कार्यक्रम चला रही है। एटरगो के अधिग्रहण से कंपनी की आरएंडडी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहां ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो पहले टेस्ला, जीएम, फेरारी, बीएमडब्ल्यू और जगुआर जैसी कंपनियों में पहले काम कर चुके हैं।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मृत्यु दर जांचने के लिए कोविड से होने वाली हरेक मृत्यु की विस्तृत जांच के आदेश दिए

मुख्यमंत्री ने ए.आई.सी.सी. की मीटिंग में बताया कि राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के ग्रुप के नेतृत्व में रोकथाम उपाय मजबूत किए

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को कहा कि उन्होंने राज्य में उच्च मृत्यु दर को समझने और इसे रोकने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कोविड से होने वाली हरेक मृत्यु की जांच करवाने के हुक्म दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माहिर टीम के नेतृत्व में महामारी को रोकने के लिए रोकथाम उपायओं को मजबूत कर रही है।

मुख्यमंत्री यह जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनीया गांधी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दे रहे थे जिसमें उन्होंने पार्टी लीडरशिप को बताया कि राज्य सरकार कोविड संकट से निपटने के लिए विशेषज्ञों के ग्रुप के नेतृत्व से काम कर रही है। विशेषज्ञों के इस ग्रुप में पी.जी.आई. के पूर्व डायरैक्टर डॉ. के.के. तलवार, बाबा फरीद मैडीकल यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज फरीदकोट के उप कुलपति डॉ. राज बहादुर, पी.जी.आई. के जन स्वास्थ्य स्कूल के पूर्व प्रमुख डॉ. राजेश कुमार से पी.जी.आई. और जोहन हौपकिंज यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ शामिल हैं।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य में उच्च मृत्यु दर का कारण पीड़ितों को कोरोना के साथ अन्य बीमारियों का होना और लोगों का स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहार है जहाँ मरीज हस्पताल में देरी से आते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 6.2 प्रतिशत की उच्च मृत्यु दर के बावजूद पंजाब में कोविड-19 के वृद्धि की दर भारत के मुकाबले कम है क्योंकि पंजाब में 16 दिनों बाद मामलों की संख्या दोगुनी हुई है जबकि राष्ट्रीय औसत के अनुसार 9 दिनों में मामलों की संख्या दोगुनी हो रही है। उन्होंने राज्य में कोविड-19 की प्रभावशाली रोकथाम का खुलासा करते हुए बताया कि 31 मार्च तक भारत के कुल मामलों में से पंजाब का हिस्सा 2.57 प्रतिशत था जोकि तीन हफ्तों बाद अब कम होकर 22 अप्रैल तक 1.22 प्रतिशत रह गया है। इसी तरह कोविड-19 की स्थिति पंजाब में बाकी देश की अपेक्षा बेहतर है।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने नवांशहर का उदाहरण दिया जहाँ प्रभावशाली ढंग से पाबंदियाँ लगाकर बेहतर नतीजे सामने आए हैं जिसकी मीडिया से भारत सरकार ने भी सराहना की है। उन्होंने मीटिंग में जानकारी देते हुए बताया कि नवांशहर जो देश के पहले हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक था, में 18 कोरोना पीड़ित मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। शुरुआत में ग्रंथी बलदेव सिंह की मृत्यु जरूर हुई थी परन्तु 26 मार्च 2020 के बाद कोई नया केस सामने नहीं आया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की तुलना केरला और गुजरात से की जानी चाहिए क्योंकि वह भी और ज्यादा एन.आर.आई. आबादी वाले राज्य हैं। उन्होंने बताया कि प्रति मिलियन आबादी के मामलों के हिसाब से गुजरात की अपेक्षा पंजाब बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ तक केरला की अपेक्षा भी कम मामले हैं (पंजाब में प्रति मिलियन 9 और केरला में प्रति मिलियन 12 मामले हैं)।

राज्य में कोविड-19 की प्रभावशाली रोकथाम का खुलासा करते हुए बताया कि 31 मार्च तक भारत के कुल मामलों में से पंजाब का हिस्सा 2.57 प्रतिशत था जोकि तीन हफ्तों बाद अब कम होकर 22 अप्रैल तक 1.22 प्रतिशत रह गया है।

पंजाब में इस समय 257 पॉजिटिव केस हैं और 16 मृत्यु हुई हैं और दो मरीजों की हालत नाजुक है जिनमें से एक वेंटिलेटर पर और दूसरा एच.डी.यू. पर है जबकि 53 मरीज इस रोग से मुक्त हुए हैं। राज्य में सीमित क्षेत्रों वाले तीन जोन हैं (जहाँ 15 से अधिक केस हैं) जिनमें जवाहरपुर, सफाबादी गेट-पटियाला, बुढ़लाडा शामिल हैं। इसी तरह तीन जिले फिरोजपुर, फाजिल्का और बठिंडा ग्रीन जोन में हैं जहाँ कोई केस नहीं है। राज्य के पास मौके के मुताबिक आइसोलेशन हस्पताल हैं।

टेस्टिंग के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 7887 टैस्ट किये गए हैं और सरकारी मैडीकल कॉलेज अमृतसर और सरकारी मैडीकल कॉलेज पटियाला में प्रति दिन 400-400 टैस्ट, सरकारी मैडीकल कॉलेज फरीदकोट और इमटैक चंडीगढ़ में प्रति दिन 150 टैस्ट और पी.जी.आई. चंडीगढ़ में प्रति दिन 60 टैस्ट करने की व्यवस्था है। इसके अलावा प्राईवेट अस्पतालों में भी टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनमें डी.एम.सी. लुधियाना में प्रति दिन 40 और तुली डायग्नॉस्टिक लैब अमृतसर में प्रति दिन 100 टैस्ट करने की सुविधा है। उन्होंने बताया कि सी.एम.सी. हस्पताल लुधियाना और एस.जी.आर.डी. मैडीकल कॉलेज, अमृतसर को टेस्टिंग की सुविधा देने की प्रक्रिया जारी है। इस समय राज्य में टेस्टिंग दर प्रति मिलियन 248 है जो राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा मामूली कम है। राष्ट्रीय टेस्टिंग प्रति मिलियन 309 है (रैपिड टेस्टिंग को छोड़कर)।

रैपिड टेस्टिंग संबंधी मुख्यमंत्री ने बताया कि आई.सी.एम.आर. द्वारा यह टैस्ट रोक देने बारे निर्देश देने से पहले राज्य में 3502 केस की जांच की गई थी। आई.सी.एम.आर. द्वारा राज्य को अब तक 10500 रैपिड टेस्टिंग किटों की सप्लाई की जा चुकी है जबकि राज्य सरकार द्वारा 10000 किटों का ऑर्डर दिया गया है जो अभी सप्लाई अधीन हैं। सरकार द्वारा और 5000 किटों के लिए भी टैंडर जारी किये गए हैं।

पंजाब सरकार ने नांदेड़ साहिब में फंसे 3000 श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी को मंजूरी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को की विनती

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने कोविड -19 के मद्देनज़र लगाई तालाबन्दी के कारण हजूर साहिब (नांदेड़, महाराष्ट्र) में फंसे राज्य के 3000 श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार को विनती की। यह प्रगटावा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने मध्य प्रदेश और राजस्थान से श्रद्धालुओं की बेरोक-टोक वापसी में सहयोग की की माँग

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र के द्वारा यह जानकारी दी है और कहा कि श्रद्धालु मध्य प्रदेश और राजस्थान से बस / सड़क के द्वारा राज्य में वापस आऐंगे। इसी तरह इन दोनों राज्यों की सरकारों और ज़िला अधिकारियों को भी श्रद्धालुओं की बेरोक-टोक वापसी के लिए सहयोग करने की विनती की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आगे बताया कि वापसी पर इन सभी श्रद्धालुओं को भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइज़री के अनुसार 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटाइन में रखा जाएगा।

न्यूज

कोरोना योद्धा आरक्षक रावत की मृत्यु पर पत्नी को सौंपा 50 लाख रुपए का चेक

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजनांतर्गत गुरुवार को राजगढ़ के आरक्षक टिंकू रावत की अंतर्राज्यीय बार्डर पर ड्यूटी के दौरान आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी श्रीमती रजनी को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कलेक्टर राजगढ़ ने गुरुवार को सांसद रोडमल नागर, विधायक कुंवर कोठार और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में मृतक की पत्नी को चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

भोपाल, (एजेंसी)। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में मध्यप्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए 'मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना-2020' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना में प्रवासी मजदूरों की जानकारी, पता, मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी एकत्रित कर तात्कालिक आवश्यकता भोजन, दवाई आदि के लिए उन्हें 1000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अप्रैल को इस योजना को घोषित किया है। अभी तक अन्य राज्यों में फंसे 15 हजार प्रवासियों की मोबाइल नंबर सूची बना ली गई है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रवासी श्रमिकों के संबंध में समन्वय स्थापित करने के लिए तय किए गए राज्य स्तरीय समन्वयक अपने-अपने निर्धारित जिलों में इसकी निगरानी करेंगे।

अर्नब पर हमला फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारों का हनन : शिवराज सिंह

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के एंकर एवं सम्पादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हमला पत्रकारिता और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारों का हनन है। श्री चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि अर्नब गोस्वामी पर हमला पत्रकारिता और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि सच्चाई का गला घोंटने के अपने कुत्सित प्रयास में कांग्रेस सफल नहीं होगी। वैचारिक मतभेद है, तो उसका जवाब विचारों से दीजिए। डराकर किसी की आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं।

सीएम हेल्पलाइन से साढ़े तीन लाख से अधिक लोगों को मिली राहत

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 आम नागरिकों और सभी जरूरतमंदों के लिये सबसे बड़ा आसरा केन्द्र बन गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस नम्बर पर अब तक 3 लाख 59 हजार 156 लोगों को फोन करने पर भोजन, राशन, दवाओं, परिवहन तथा अन्य प्रकार की राहत उपलब्ध कराई गई है। सीएम हेल्पलाइन किसानों के लिये भी मददगार साबित हो रही है। इस पर अब तक किसानों की फसल कटाई, फसल परिवहन आदि की 976 समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया गया है। सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 पर अब तक भोजन संबंधी 2 लाख 80 हजार 767, परिवहन संबंधी 18 हजार 489, दवाइयों संबंधी 24 हजार 785, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी आदि संबंधी 12 हजार 056 तथा अन्य प्रकार की 23 हजार 059 समस्याओं की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर सहायता मुहैया कराई गई।

राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष बना नागरिकों का मददगार

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों, जिज्ञासाओं आदि के त्वरित समाधान के लिये विशेष राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) भोपाल के स्मार्ट सिटी सेंटर में संचालित किया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस नियंत्रण कक्ष को प्राप्त 23 हजार 962 फोनकॉल में से 21 हजार 413 में त्वरित कार्रवाई कर समाधान किया गया। नियंत्रण कक्ष द्वारा किये जा रहे सहयोग एवं सहायता से अब तक दो लाख 24 हजार 743 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य-स्तरीय नियंत्रण-कक्ष को राशन, भोजन, आश्रय, चिकित्सा, परिवहन तथा अन्य प्रकार की सहायता एवं सहयोग के लिये प्राप्त होने वाले फोनकॉल को तीन अलग-अलग श्रेणी में दर्ज कर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश के वह नागरिक जो अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं, से प्राप्त 14 हजार 465 फोनकॉल में से 12 हजार 513 का निराकरण किया गया। प्रदेश के अन्दर ही अपने निवास के जिले से बाहर रुके हुए नागरिकों से प्राप्त 7 हजार 424 फोनकॉल में से 7 हजार 100 को वांछा गया सहयोग प्रदान किया गया।

पूर्व आईएएस समेत आठ लोगों पर कर्फ्यू उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज

शिमला, (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लॉकडाउन और कर्फ्यू के उल्लंघन के आरोप में पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामला सुन्नी थाने में दर्ज किया गया है तथा दो वाहन भी जब्त किए हैं। सुन्नी के लोगों ने पुलिस को सूचित किया कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान दो वाहनों में कुछ लोग वहां पहुंचे हैं। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुये खटनोल के निकट दोनों वाहनों को रोक लिया। इनमें पूर्व आईएएस अधिकारी समेत आठ लोग सवार थे। पुलिस पूछताछ में इन्होंने बताया कि वे शाली माता मंदिर से लौट रहे थे लेकिन वे किसी प्रकार की अनुमति सम्बंधी दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा पाए। पुलिस ने इस सम्बंध में मामला दर्ज कर लिया है।

हमीरपुर में तहसीलदार पर हमला करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

हमीरपुर,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की हीमरपुर पुलिस ने जरिया क्षेत्र में खदान की जांच के दौरान तहसीलदार और उनके गनर पर हमला करने के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को जांच के दौरान चंडौत मौरंग खदाने के पास करीब कुछ लोगों ने तहसीलदार हेमंत चौधरी के गनर बीरेंद्र और उनके चालक अलकेश को लाठी डंडो से मारपीट कर घायल कर दिया था जबकि तहसीलदार ने किसी तरह भाग कर जान बचायी थी। पुलिस ने गुरुवार को गांव में छापा मारकर मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र और उसके साथी मानसिंह, चेतन,कपिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

वैज्ञानिक तरीके से गेहूं भंडारण में अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश

साइलो पद्धति से होगा 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। प्रदेश की 289 सहकारी समितियों के एक लाख 81 हजार से अधिक किसानों से उपार्जित 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण 25 साइलो बैग और स्टील साइलो में किया जा रहा है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि साइल बैग ओर स्टील साइलो खाद्यान्न भंडारण की आधुनिकतम तकनीकी है। इस तकनीकी में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक औषधियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। इसमें गेहूं बिना कीटनाशक के उपयोग के भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भोपाल , सीहोर , विदिशा , होशंगाबाद, नागौद , सतना हरदा, उज्जैन और देवास में 50- 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले स्टील साइलो केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनकी कुल भंडारण क्षमता साढ़े चार लाख मीट्रिक टन है। इसी प्रकार नागदा, सलमानीया बड़ौदा, पिछोर, बैरसिया श्यामपुर गमाखर, गोहरगंज, शुक्रवारा, बरपटी, हटा, बरछा, मझौली, सारंगपुर, तथा वेदगबा भंडारण केन्द्रों की कुल भंडारण क्षमता 6 लाख 30 हजार मीट्रिक टन है।

श्री शुक्ला ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को बनाए रखने में साइलो बैग पद्धति, भंडारण की आदर्श व्यवस्था सिद्ध हो रही है। इस व्यवस्था में भंडारण का काम न्यूनतम मानव श्रम से संभव हो सका है। इसमें किसान जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली या एक ट्रक में खाद्यान्न लेकर अकेला केन्द्र पर पहुंचता है, तो धर्म-कॉटे पर तौल करने के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा एक ही बार में उसका पूरा गेहूं भंडारण के लिए खाली करा लिया जाता है। इस तरह किसान अधिकतम 15 से 20 मिनट के अंदर अपना गेहूं बेच कर फ्री हो जाते हैं। इस कारण इन केन्द्र पर भीड़-भाड़ होने या अधिक मात्रा में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना नगण्य रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी केंद्रों पर हैंड वॉश सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

सरकार किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदेगी : सीएम

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों से कहा है कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों की गेहूं एवं अन्य रबी फसलों को खरीदने का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया है। किसान मोबाइल पर एसएमएस से सूचना मिलने पर ही खरीदी केंद्र पर निर्धारित दिनांक को ही अपनी फसल बेचने आएं।

श्री चौहान ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, बार-बार हाथ धोना तथा पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना संकट के इस समय में सरकार द्वारा किसानों को सौदा पत्रक के माध्यम से भी अपनी फसल व्यापारियों को सीधे बेचने की सुविधा भी प्रदान की गई है। किसान मंडियों के बाहर भी सौदा पत्रक के माध्यम से अपनी उपज पंजीकृत व्यापारियों को अपने घर पर ही अथवा निजी केन्द्रों पर बेच सकते हैं। उपज का सही मूल्य मिले, तभी सौदा पत्रक पर सहमति दें। आपके पास समर्थन मूल्य का सुरक्षा कवच है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे लॉक डाउन का पूरा पालन करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें। मास्क ना हो तो गमछे का प्रयोग करें। खरीदी केन्द्रों पर पर्याप्त दूरी बनाकर अपनी रबी फसल बेचें।

भारत की विकास यात्रा में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज मंत्री तोमर को लिखा पत्र

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभा रहे सभी लोगों को बधाई दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को गुरुवार को भेजे गए एक पत्र में श्री मोदी ने कहा है कि पंचायतें ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रभावी माध्यम हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भारत की विकास यात्रा में प्रभावी भूमिका निभा रहे सभी लोगों को पंचायती राज दिवस की बहुत-बहुत बधाई।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

पत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिखा है, महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि एक सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के विकास की कुंजी है। गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए कदम हमारे इसी संकल्प को दर्शाते हैं। चाहे हर गांव तक बिजली पहुंचाना हो या गांवों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में उठाए गए कदमए चाहे उज्ज्वला योजना के जरिए गांवों में माताओं और बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना हो या जन.धन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना या फिर खादए बीजए पानीए मिट्टीए बाजार से लेकर सड़कए शिक्षाए स्वास्थ्यए कौशल और रोजगारए समग्र प्रयासों से आज गांव देश के सतत और तेज विकास के भागीदार और साक्षीए दोनों बन रहे हैं। आज हम अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैंए जब कोरोना महामारी पूरी मानवता के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे में हम सभी भारतीय पूरी एकजुटता के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के वे सभी सदस्य हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है जो इस महामारी से निपटने के लिए वीर योद्धाओं की तरह पूरे समर्पण के साथ कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही सामूहिक शक्ति इस लड़ाई में हमारा संबल है। समस्त देशवासियों के धैर्यए अनुशासनए सहयोग और सजगता के जरिए हम अवश्य कोरोना महामारी को परास्त कर पाएंगे। एक बार पुनरू आप सभी को पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाई।

प्रधानमंत्री आज करेंगे ई-ग्राम स्वराज एकीकृत पोर्टल का उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ई.ग्राम स्वराज नामक एक एकीकृत पोर्टलए जिसमें पंचायत स्तर पर नियोजनए अनुश्रवणए वित्त प्रबंधन तथा ऑडिट की सुविधा उपलब्ध है, का उदघाटन करेंगे। साथ ही राज्य सरकारों तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय ने ड्रोन आधारित नवीनतम सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए स्वामित्व नामक नई केंद्रीय योजना शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया हैए जिसका शुभारंभ भी इस मौके पर प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी करेंगे। मंत्री श्री तोमर ने भी देशभर के सभी पंचायत प्रतिनिधियों और गांवों के विकास में सहभागी समस्त लोगों को पंचायती राज दिवस की बधाई दी है।

इस समय दहेज प्रताड़ना, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे अपराधों की संख्या में आई है कमी

पंजाब में घरेलू हिंसा की घटनाओं में 21 फीसदी वृद्धि

चंडीगढ़, (एजेंसी)। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले एक महीने से लागू लॉकडाउन का एक दुष्प्रभाव महिलाओं के खिलाफ अपराधों और घरेलु हिंसा की घटनाओं में वृद्धि के रूप में सामने आया है और पंजाब पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में 21-21 फीसदी की वृद्धि हुई है।

लॉकडाउन के दुष्प्रभाव

पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता के गुरुवार को यहां जारी बयान के अनुसार पंजाब पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घरेलु हिंसा की घटनाओं से निबटने के लिए एक विस्तृत रणनीति बनाई है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोजाना कार्रवाई रिपोर्ट पुलिस उपाधीक्षक ले रहे हैं। पंजाब पुलिस के अनुसार फरवरी से अप्रैल महीने तक के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या 4709 से बढ़कर 5695 हो गई है और इसी तरह महिलाओं के खिलाफ घरेलु हिंसा के मामले 3287 से बढ़कर 3993 हो गए हैं। पंजाब पुलिस के अनुसार दूसरी तरफ दहेज प्रताड़ना, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे अपराधों की संख्या में इस अवधि में कमी आई है और उसकी वजह संभवतः महिलाओं व पुरुषों का घरों से अधिक न निकलना तथा सड़कों पर पुलिसकी बढ़ी उपस्थिति है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मार्च व अप्रैल के दौरान डायल 112 पर मिलने वाले कॉल की औसत संख्या एक दिन में 133 हो गई, जो घरेलु हिंसा मामलों में 34 प्रतिशत की वृद्धि है। पिछले तीन महीनों में यह औसत प्रति दिन 99.33 कॉल थी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में वृद्धि इस अवधि में 30 फीसदी है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने आज महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने वाले प्रकोष्ठ के सभी उपाधीक्षकों और महिला सहायता डेस्क अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिसमें सहायक पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक मामले विभाग) गुरप्रीत देव ने एक रणनीति पेश की। ऐसी घटनाओं पर पुलिस के प्रतिसाद को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिये गये हैं।

बैठक में तय किया गया कि उपाधीक्षक (सीएडब्ल्यू) प्रति दिन ऐसी शिकायतों की रिपोर्ट भेजेंगे और उन्हें लेकर की गई कार्रवाई पर निगरानी रखेंगे। पुलिस 'वन स्टॉप सेंटर' से समन्वय बनाए रखेगी जिनमें कि सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला एवं बाल कल्याण की तरफ से नामित सलाहकार होते हैं। इनकी सेवाएं, जहां आवश्यकता पड़े, पीड़ितों, हिंसा करने वालों से बात करने के लिए और बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ली जाएंगी।

पीड़ितों की मदद करेगी महिला सहायता डेस्क

रणनीति के अनुसार तैयार कार्यप्रणाली इस तरह होगी कि 112 पर कॉल मिलते ही, विवरण जिला नियंत्रण कक्ष को फॉरवर्ड किया जाएगा और उसका विवरण सीएडब्ल्यू उपाधीक्षक व जिला महिला सहायता डेस्क को दिया जाएगा। महिला सहायता डेस्क की टीमें पीड़ित महिलाओं से मिलेंगी। पुलिस थानों में तैनात महिला कांस्टेबल शिकायतों का निबटारा पुलिस स्टेशन व जिला स्तरीय हेल्प डेस्क के साथ मिलकर करेंगी। संकटग्रस्त महिलाओं से तुरंत फोन पर भी बात की जाएगी और जरूरत पड़ी तो मिलकर उनसे, उनके पति या परिजन से मिलकर परामर्श दिया जाएगा। यदि कोई महिला मायके या शेल्टर होम जाना चाहती है तो उसकी मदद की जाएगी। शारीरिक शोषण के मामलों में चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जाएगा और थाना प्रभारी से मिलकर आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

माता शीतला देवी बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए पांच करोड़ रुपए

गुरुग्राम, (एजेंसी)। कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए स्थानीय श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड ने हरियाणा के मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में पांच करोड़ रुपए की राशि दान दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के मुख्य प्रशासक विनय प्रताप सिंह ने बताया कि संकट की इस घड़ी में सभी को एकजुट होकर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष बनाया गया है जिसका उपयोग जरूरतमंद और गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लॉक डाउन के दौरान किसी भी गरीब व्यक्ति को भूखे पेट न सोना पड़े। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने सामर्थ्य अनुसार गरीब लोगों की मदद करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.